

सम्पादकीय

डिजिटल संसार में अत्यधिक समय देना सेहत का जोखिम

यह मानव स्वभाव है कि हर पीढ़ी अपने बच्चों को खुद से अधिक सुविधाएं देने का प्रयास करती है। मगर ऐसा लगता है कि आज की हमारी पीढ़ी ने अपने बच्चों को पूरी दुनिया एक छोटी सी स्क्रीन में सौंप दी है। बच्चे अब पहाड़, समुद्र, युद्ध, महामारी और उत्सव सब वुछ अंगुलियों के एक स्पर्श से देख सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या दुनिया को समझ भी पा रहे हैं? या फिर सिंप देख रहे हैं, बिना याद रखे, बिना गहराई से बेड किए? इसी प्रश्न के बीच दो नई आदतें उभरकर सामने आती और स्त्रॉलिंग संस्क्रुति, जो बच्चों की दृश्य स्मृति मानसिक सक्रियता को प्रभावित कर रही है। हूबेड-राटिंगहू का अर्थ हैलंबे समय तक बिस्तर पर ही पड़े रहना और मोबाइल चलाते रहना। पढ़ाई, मोबाइल, आराम सब वुछ एक ही जगह पर यह आदत अकसर थकान उदासी के नाम पर शुरू होता है रू होती है, लेकिन धीरे-धीरे जीवनशैली बन जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार, जब बिस्तर केवल सोने की जगह न रहकर जागने और स्त्रीन देखने का वेद्र बन जाता है, तो दिमाग को स्पष्ट संकेत नहीं मिलते।। इसका सीधा असर नींद की गुणवत्ता और स्मृति निर्माण की प्रीया पर पड़ता है। बच्चों के मामले में यह स्थिति और भी संवेदनशील है। उनका दिमाग अभी विकसित हो रहा होता है। विजुअल प्रोसेसिंग यानी दृश्य प्रसंस्करण वह क्षमता है, जिससे बच्चा आकार, रंग, दूरी, दिशा और गति को समझता है। दृश्य स्मृति वह शक्ति है, जिससे वह देखी हुई जानकारी को याद रखता है, चाहे वह शब्दों का रूप हो, किसी का चेहरा हो या रास्ते की पहचान। इन क्षमताओं का विकास केवल किताबों या स्त्रीन से नहीं होता, बल्कि वास्तविक दुनिया के अनुभवों से होता है, जैसे खुली जगह, खेल, दौड़ना, चेहरे पढ़ना, , और वस्तुओं को छूकर समझना आदि। लगातार बिस्तर पर रहकर एक सीमित दूरी से स्त्रीन देखना दृश्य अनुभव को संवुचित कर देता है। ऐसे में बच्चा तेज, चमकीली और लगातार बदलती तस्वीरों का आदी हो जाता है। तंत्रिका तंत्र विज्ञान से जुड़े शोध बताते हैं कि इस तरह के एकरूप दृश्य अनुभव से मस्तिष्क के ध्यान वेद्रित करने की क्षमता और दृश्य विशेष कौशल कमजोर हो सकता है। इसका असर आगे चलकर पढ़ने-लिखने और समझने की क्षमता पर भी दिखता है। इसी सीमित दृश्य संसार में प्रवेश करती है हूब्स स्त्रॉलिंगहू यानी नकारात्मक, डराने वाली और संकेत से भरी सूचनाओं को बिना रुके देखते जाना महामारी, युद्ध, अपराध और आपदाओं की लगातार तस्वीरें बच्चों और किशोरों के मन में यह भावना बैठा देती हैं कि दुनिया असुरक्षित और भयावह है। अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों के अनुसार, इस तरह की आदत दिन, अवसाद और मानसिक थकान बढ़ाती है। च्चित दिमाग न तो ध्यान वेद्रित कर पाता है और न ही नई जानकारी को ठीक से याद रख पाता है। इसके विपरीत हाल के वर्षों में हूब्लूम-स्त्रॉलिंगहू की अवधारणा सामने आई है, यानी सकारात्मक, प्रेरक और ज्ञानवर्धक सामग्री को चुनकर देखना सही तरीके से अपनाया जाए, तो यह बच्चों में जिज्ञासा, आशावाद और रचनात्मक सोच को बढ़ा सकता है। लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश डिजिटल मंच बच्चों को सोच-समझकर चुनने की बजाय लगातार सॉल करते रहने के लिए डिजाइन किए गए हैं।

खाटू श्याम पर लॉरेंस बिश्नोई की नजर! कोषाध्यक्ष के बेटे से ₹3 करोड़ की रंगदारी मांगी

(जीएनएस)। दुनियाभर में श्याम भक्तों की गहरी आस्था से जुड़े खाटू श्यामजी मंदिर ट्रस्ट पर अब खतरनाक लॉरेंस बिश्नोई गैंग की नजर है। इस मंदिर को देश-दुनिया के भक्तों से चढ़ावा और दान मिलता है। मंदिर के पूर्व कोषाध्यक्ष के बेटे को इंटरनेशनल नंबर से धमकी भरा कॉल आया है। कुख्यात गैंग के नाम पर रंगदारी की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। खाटू श्याम मंदिर समिति के पूर्व कोषाध्यक्ष कालू सिंह के पुत्र मानवेंद्र सिंह चौहान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता ने बताया कि रंगदारी की कॉल करनेवाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का सदस्य बताया और तीन करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी है। इतना ही नहीं यह भी धमकी दी है कि अगर समय पर पैसे नहीं दिए, तो खतरनाक अंजाम भुगतना पड़ सकता है। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार



दहशत में है। पीड़ित का कहना है कि कॉलर का लहजा और अंदाज बेहद आक्रामक था। उसने खुद को खतरनाक गैंग से जुड़ा हुआ बताया और परिवार के सदस्यों की डिटेल भी शेयर की। पीड़ित का कहना है कि कॉलर ने परिवार के सदस्यों की रूटीन और आने-जाने की डिटेल की निगरानी की भी बात कही थी। बदमाश ने धमकी देते हुए कहा कि

इस वर्ष राजकोट में आयोजित होने वाली दूसरी वाइब्रेंट गुजरात - पुलिस का मानना है कि कई मामलों में यह साइबर अपराधी या स्थानीय बदमाश हो सकते हैं। शरात के लिए कुख्यात गैंग के नाम का इस्तेमाल कर लोगों को भयभीत करने की कोशिश भी हो सकती है। पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। पुलिस ने दर्ज किया केस, जांच में जुटी पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हमने केस दर्ज कर लिया है और मामले की पड़ताल चल रही है। तकनीकी साक्ष्य और संभावित नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की धमकी भरी कॉल या संदिग्ध संदेश मिलने पर धरपार नहों। ऐसी किसी भी कॉल पर साइबर सेल और पुलिस को सूचना दें। फिलहाल यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है

पटना में रोड पर थूकने वाले देंगे जुमाना, चौराहे पर लगेगी फोटो, पेशाब करने पर भी एक्शन

(जीएनएस)। अगर आप बिहार पटना में रहते हैं या यहां आते-जाते हैं, तो अब यह खबर आपके लिए जरूरी है। सड़क पर पान-गुटखा खाकर थूकना या सार्वजनिक जगहों पर पेशाब करना अब मामूली बात नहीं रही। नीतीश सरकार और पटना नगर निगम ने मिलकर ऐसे लोगों के लिए ऐसा "इलाज" तय किया है, जिसे सुनकर ही कई लोग संभल जाएंगे। जुमाना भी लगेगा और इज्जत भी दांव पर होगी। पटना को साफ-सुथरा और रहने लायक शहर बनाने की दिशा में पटना नगर निगम ने सख्त फैसला लिया है। सड़क, फ्लाईओवर, चौराहा या कोई भी सार्वजनिक जगह हो, अगर कोई थूकने या गंदगी फैलाते पकड़ा गया, तो तुरंत कार्रवाई होगी। इस फैसले का मकसद पटना को सिंगापुर जैसे स्वच्छ शहर की दिशा में आगे बढ़ाना है। दइल्लं रसइ३इल्लं फइ३ पटना में थूकते पकड़े गए तो 500 रुपये जुमाना, फोटो होगी

सार्वजनिक पेशाब करने वालों पर भी नगर आयुक्त सह पटना स्मार्ट सख्त कार्रवाई इतना ही नहीं, ऐसे व्यक्ति की सिटी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक यशपाल मीणा के निर्देश पर यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अब अगर कोई व्यक्ति खुले में पान, गुटखा या तंबाकू खाकर थूकते हुए पकड़ा गया, तो उससे मौके पर ही 500 रुपये का जुमाना वसूला जाएगा। इतना ही नहीं, ऐसे व्यक्ति की तस्वीर शहर के प्रमुख चौराहों पर लगी बैरिएबल मैसेज डिस्प्ले (रेडऊ) स्क्रीन पर दिखाई जाएगी। यानी अब गंदगी फैलाने वालों को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ेगा। नगर निगम ने ऐसे लोगों को सीधे तौर पर "नगर शत्रु" यानी शहर का दुश्मन घोषित किया है। सिर्फ थूकने वालों पर ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्थानों पर पेशाब करने वालों पर भी अब शिकंजा कसा जाएगा। नगर निगम की प्रवर्तन टीमों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि खुले में पेशाब करते पाए जाने पर तुरंत जुमाना लगाया जाए। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की हरकतों से शहर के कई इलाके रेड स्पाॅट बन चुके हैं, जिससे न सिर्फ गंदगी बढ़ती है, बल्कि आम लोगों की सेहत पर भी असर पड़ता है। 3300 CCTV कैमरों से 24 घंटे नजर इस पूरे अभियान की रीढ़ है पटना

वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) कच्छ सौराष्ट्र में मोरबी सिरेमिक क्लस्टर को विशेष जोन के रूप में पेश किया जाएगा 9 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार देता है मोरबी का सिरेमिक उद्योग पॉलीपैक इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में भी मोरबी बन सकता है गुजरात का अग्रणी ज़िला गांधीनगर, 05 जनवरी : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में गुजरात वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) कच्छ-सौराष्ट्र के दूसरे संस्करण के लिए तैयार हो रहा है। 11 एवं 12 जनवरी, 2026 के दौरान राजकोट में होने वाली वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस कच्छ एवं सौराष्ट्र के हिस्से के रूप में राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। सिरेमिक उद्योग का अगुवा, गुजरात का मोरबी जिला आज भारत की सिरेमिक अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ बन गया है। गुजरात के कुल सिरेमिक उत्पादन में अकेले लगभग 90 फीसदी हिस्सेदारी के साथ मोरबी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिरेमिक उत्पादन केंद्र है। कुम्हार के चाक से वैश्विक सिरेमिक हब तक : मोरबी की उद्योग गाथा मोरबी आज देश और दुनिया में सिरेमिक उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। शुरुआत में यहां

पारंपरिक तरीके से मिट्टी के मटके, दीये, खपरैल और घरेलू मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। स्थानीय मिट्टी की गुणवत्ता और कारीगरों की कुशलता ने मोरबी के उत्पादों को एक नई पहचान दी। बाद में, वॉल क्लॉक (दीवार घड़ी) उद्योग की शुरुआत हुई।



समय के साथ-साथ, 1970-80 के दशक में रूफ टाइल्स और ग्लेज्ड टाइल्स का उत्पादन शुरू हुआ और धीरे-धीरे मोरबी आधुनिक सिरेमिक उद्योग की दिशा में आगे बढ़ा। नई टेक्नोलॉजी, उन्नत मशीनरी और उद्यमिता के दृष्टिकोण ने इस शहर को सिरेमिक उद्योग के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान दी। आज मोरबी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और विट्रिफाइड टाइल्स के उत्पादन के लिए वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध है। मोरबी का सिरेमिक सफर परंपरा से प्रगति की ओर बढ़ने का बेजोड़ उदाहरण बन गया है। गुजरात का मोरबी जिला बना भारत का सिरेमिक हब

रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) कच्छ-सौराष्ट्र में मोरबी के सिरेमिक क्लस्टर की एक विशेष प्रदर्शनी होगी, जिसमें 'अद्यतन सिरेमिक्स', 'वैल्यू-एडेड प्रोडक्ट्स', 'एनर्जी-एफिशिएंट टेक्नोलॉजी' और नए 'सिरेमिक पार्क' की प्रगति मुख्य आकर्षण होंगे। राज्य



सरकार उद्योगों के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ऑटोमेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट रिसाइक्लिंग और लॉजिस्टिक्स सुपोर्ट बढ़ाने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। मोरबी के उद्यमियों के परिश्रम, सरकार की प्रभावी नीतियों और गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता के कारण आज मोरबी भारत की 'सिरेमिक राजधानी' बन गया है।

मोरबी का सिरेमिक उद्योग लगभग 9 लाख लोगों को देता है रोजगार

मोरबी जिले का सिरेमिक क्लस्टर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिरेमिक उत्पादों का उत्पादन करने वाला क्लस्टर है। मोरबी जिले में लगभग

1 फरवरी को नहीं पेश होगा इस बार का बजट? डेट को लेकर सस्पेंस?

(जीएनएस)। वित्त वर्ष 2026-27 के आगामी आम बजट को लेकर देशभर में चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस बार उत्सुकता केवल नई योजनाओं को लेकर नहीं, बल्कि बजट (वल्लड्वल्ल इश्री३ 2026) पेश होने की तारीख को लेकर भी है। दरअसल, साल 2026 में 1 फरवरी को रविवार पड़ रहा है, जिससे यह सवाल खड़ा हो गया है। सवाल ये है कि क्या संसद की कार्यवाही छुट्टी के दिन होगी या इसे 2 फरवरी, सोमवार के लिए टाला जाएगा? इसके अलावा, उसी दिन गुरु रविदास जयंती भी है, जो दिल्ली सहित कई राज्यों में एक प्रतिबंधित अवकाश है। इसके जुड़े तमाम सवालों के जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं।

1 फरवरी की तारीख पर क्यों बना है संशय? भारत में बजट पेश करने की परंपरा में 2017 में बड़ा बदलाव आया था। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट को फरवरी के अंत के बजाय 1 फरवरी को पेश करने की शुरुआत की थी। इस बार 1 फरवरी 2026 को रविवार होने के कारण दो संभावनाओं

1200 सिरेमिक इकाइयां हैं, जिनका कुल सालाना उत्पादन लगभग 60 लाख टन है। ये इकाइयां करीब 9 लाख लोगों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से रोजगार प्रदान करती हैं।

गत दो वर्षों के दौरान लाभार्थियों को मिला विभिन्न सरकारी सहायता



योजना का लाभ

मोरबी जिले में गत दो वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी सहायता योजनाओं के तहत व्यापक और प्रभावी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, जो जिले के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम सिद्ध हो रही है। राज्य सरकार की विभिन्न औद्योगिक प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान लगभग 2200 से अधिक लाभार्थियों को सीधे 115 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता पहुंचाई गई है। इस सहायता से मोरबी जिले के नागरिकों को स्वरोजगार, उद्योग, जीवन स्तर में सुधार और

आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ने के नए अवसर मिले हैं, जो राज्य सरकार की जनकल्याण की प्रतिबद्धता और सर्वांगीण विकास के दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करता है।

भारत के कुल सिरेमिक निर्यात में लगभग 80 से 90 फीसदी का योगदान



मोरबी का सिरेमिक उद्योग वैश्विक बाजार में गुजरात तथा भारत की मजबूत पहचान बन रहा है। अनुमान के मुताबिक वर्ष 2024-25 के दौरान मोरबी से लगभग 15,000 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ। खास बात यह है कि अकेला मोरबी भारत के कुल सिरेमिक निर्यात में 80 से 90 फीसदी का योगदान देता है। यहां बनाए जाने वाले उच्च गुणवत्ता के सिरेमिक टाइल्स और संबंधित उत्पादों को मुख्य रूप से अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ओमान और श्रीलंका जैसे देशों में निर्यात किया जाता है, जो मोरबी की वैश्विक विश्वसनीयता और 'मेड इन इंडिया-मेड इन गुजरात' ब्रांड की मजबूत स्थिति को साफ तौर पर

उजागर करता है।

पॉलीपैक उद्योग के क्षेत्र में भी मोरबी बन सकता है राज्य का अग्रणी जिला

गुजरात का मोरबी जिला सिरामिक क्षेत्र की तरह ही पॉलीपैक उद्योग के क्षेत्र में भी निकट भविष्य में राज्य का एक अग्रणी जिला बन सकता है। अभी मोरबी जिले में पीपी (पॉलीप्रोपाइलिन) वूवन प्रोडक्ट की कुल 150 इकाइयां कार्यरत हैं। मोरबी का पॉलीपैक उद्योग अभी सालाना लगभग 5 लाख मीट्रिक टन पीपी वूवन फैब्रिक का उत्पादन करता है, जिसका कुल सालाना टर्नओवर लगभग 5500 करोड़ रुपए है। पॉलीपैक उद्योग आज मोरबी के लगभग 25 से 20 हजार लोगों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है।

भारत के वॉल क्लॉक उत्पादन में मोरबी जिले की बड़ी हिस्सेदारी सिरेमिक तथा पॉलीपैक के जैसे ही वॉल क्लॉक और गिफ्ट आर्टिकल उद्योग भी मोरबी में बड़े पैमाने पर विकसित हुआ है। भारत के वॉल क्लॉक उत्पादन में मोरबी जिले के वॉल क्लॉक तथा गिफ्ट आर्टिकल उद्योग की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। मोरबी जिले में वॉल क्लॉक की लगभग 150 से 200 इकाइयां हैं। ये उद्योग करीब 10 से 12 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार प्रदान करते हैं, जिनमें से 60 फीसदी महिलाएं हैं।

पर विचार किया जा रहा है:

संडे बजट: संसदीय परंपराओं के अनुसार, विशेष परिस्थितियों में संसद की बैठक रविवार को बुलाई जा सकती है। 1999 में यशवंत सिन्हा ने रविवार (28 फरवरी) को बजट पेश किया था।

2 फरवरी का विकल्प: यदि कैबिनेट कमेट्री ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स (CCPA) फैसला लेती है, तो इसे सोमवार तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।

बजट 2026 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। यदि वह इस बार बजट पेश करती हैं, तो वे लगातार 9 बार बजट पेश करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी।

मोराजी देसाई का रिकॉर्ड: पूर्व प्रधानमंत्री मोराजी देसाई ने कुल 10 बार बजट पेश किया था, लेकिन उन्होंने यह दो अलग-अलग कार्यकालों (1959-64 और 1967-69) में किया था।

लगातार बजट: निर्मला सीतारमण

अब तक लगातार 8 बजट (एक अंतिम सहित) पेश कर चुकी हैं। इस साल का बजट उन्हें पी. चिदंबरम (9 बजट) और प्रणब मुखर्जी (8 बजट) जैसे दिग्गजों की फेहरिस्त में सबसे ऊपर ले जाएगा।

छुट्टी के दिन बजट, क्या कहता है इतिहास? वीके 'ड पर बजट पेश करना केंद्र सरकार के लिए नई बात नहीं है। मोदी

सरकार ने पहले भी कई बार छुट्टी या शनिवार के दिन बजट पेश कर अपनी प्रतिबद्धता जताई है:

2025 का बजट: शनिवार को पेश किया गया था।

2015 और 2016 का बजट: अरुण जेटली ने शनिवार, 28 फरवरी 2015 और 29 फरवरी 2016 को पेश किया था।

ब्रिटिश काल की परंपरा: जानकारों के अनुसार, रविवार को बजट पेश करने की जड़ें ब्रिटिश काल से जुड़ी हैं, इसलिए तकनीकी रूप से इसमें कोई बाधा नहीं

बांग्लादेश में इस पार्टी की बन सकती है सरकार, ओपिनियन पोल से बड़ी यूनूस की टेंशन

(जीएनएस)। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले 13वें आम चुनाव से पहले सियासी सरगमी चरम पर है। कड़के की ठंड के बीच जारी ताजा ओपिनियन पोल ने देश के राजनीतिक भविष्य की एक स्पष्ट तस्वीर पेश की है। सर्वे के चौंकाने वाले नतीजों के अनुसार, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग के पतन के बाद अब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करती दिख रही है। करीब 70 प्रतिशत मतदाताओं का समर्थन हासिल कर इटठ ने अपने प्रतिद्वंद्वी जमात-ए-इस्लामी को काफी पीछे छोड़ दिया है। यह चुनाव न केवल बांग्लादेश, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की भू-राजनीति के लिए निर्णायक साबित होने वाला है। एमिनेंस एसोसिएट्स द्वारा कराए गए मेगा सर्वे ने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। देश के सभी 300 संसदीय क्षेत्रों में हुए इस पोल के मुताबिक, 70

घोषणा होगी। राजनीतिक विरासत को संभालते हुए तारिक रहमान अपना चुनावी अभियान सिलहट से शुरू करेंगे, जो उनकी मां खालिदा जिया का यह है कि आवामी लीग के पारंपरिक वोट बैंक में भी बड़ी संघ लगी है। उनके 60 प्रतिशत पुराने समर्थक अब इटठ की ओर रुख कर चुके हैं, जो पार्टी की ऐतिहासिक जीत का संकेत है। तारिक रहमान की ताजपोशी और चुनावी शंखनाद पार्टी के कार्यवाहक नेता तारिक रहमान के लिए यह समय सजीवनी जैसा है। ओपिनियन पोल के सकारात्मक रूझानों के बीच BNP उन्हें औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारी पूरी कर चुकी है। महासचिव फखरुल इस्लाम आलमगीर ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही इसकी

पारंपरिक गढ़ रहा है। इस कदम को समर्थकों को एकजुट करने के भावनात्मक कार्ड के रूप में देखा जा रहा है। अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार को उखाड़ फेंकने वाले छत्र आंदोलन से भारी उम्मीदें थीं, लेकिन चुनावी मैदान में वे फकीरी पड़ती दिख रही हैं। आंदोलन से निकली 'नेशनल

सिटिजन्स पार्टी' (NCP) को सर्वे में मात्र 2.6 प्रतिशत लोगों का साथ मिला है। यह नतीजे बताते हैं कि सड़कों पर दिखने वाला जन-आक्रोश हमेशा स्थायी राजनीतिक समर्थन में नहीं बदलता। बांग्लादेश की जनता फिलहाल नए प्रयोगों के बजाय स्थापित और अनुभवी नेतृत्व (BNP) पर अधिक भरोसा जताती नजर आ रही है। बांग्लादेश का यह चुनाव केवल घरेलू बदलाव नहीं, बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का भी मामला है। शेख हसीना के भारत के साथ करीबी रिश्तों के बाद, अब इटठ की संभावित वापसी नई दिल्ली और बीजिंग दोनों के लिए कूटनीतिक चुनौतियां और अवसर लेकर आएगी। आवामी लीग के बिखराव और जमात-ए-इस्लामी की सीमित बढ़त के बीच, 12 फरवरी को होने वाला मतदान यह तय करेगा कि बांग्लादेश लोकतंत्र की राह पर आगे बढ़ेगा या धार्मिक कट्टरवाद और राजनीतिक अस्थिरता के एक नए दौर में प्रवेश करेगा।

डीजीपी/एसपी ने समाधान दिवस पर कलीनगर तहसील में जन शिकायतें सुनीं,भूमि विवादों में राजस्व-पुलिस संयुक्त टीम के निर्देश दिए

(जीएनएस)। पीलीभीत सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक (DIG/SP) पीलीभीत ने तहसील कलीनगर में पहुंचकर जनता की समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुना। उन्होंने विभिन्न शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। विशेष रूप से भूमि विवादों के मामलों में राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर निष्पक्ष जांच व कार्यवाही करने का आदेश जारी किया गया। इस अवसर पर रह ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जन शिकायतों



का निपटारा निर्धारित समयसीमा के भीतर किया जाए तथा कोई भी मामला लंबित न रहे। भूमि विवादों को लेकर ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही परेशानियों का समाधान करने के लिए राजस्व और पुलिस टीमों के समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ

ही सभी शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान हो, ताकि आम जनता को न्याय मिल सके।

कलीनगर तहसील में आयोजित इस समाधान दिवस में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित हुए, जिन्होंने अपनी समस्याएं रह के समझ रखीं। रह ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए और कई मामलों में तत्काल कार्रवाई के आदेश भी जारी किए। यह आयोजन जिला प्रशासन की जनोन्मुखी नीति का हिस्सा है, जो समय-समय पर आयोजित होकर आम लोगों की परेशानियों का निवारण करता है।

सुनगढ़ी पुलिस ने मिशन शक्ति-5 के तहत थाना क्षेत्रान्तर्गत व्यापक भ्रमण कर बालिकाओं व महिलाओं को किया जागरूक

(जीएनएस)। पीलीभीत। DIG/एसपी पीलीभीत के निर्देशन में चल रहे मिशन शक्ति-5 अभियान के तहत थाना सुनगढ़ी पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत व्यापक भ्रमण कर बालिकाओं व महिलाओं को जागरूक किया गया। पुलिस टीम ने मोहल्लों व सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचकर महिला सम्बन्धी अपराधों, छेड़खानी, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, स्टॉकिंग आदि से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत पुलिस से संपर्क करने की अपील की। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान महिला व पुरुष पुलिसकर्मियों ने प्रतिभागी बालिकाओं/महिलाओं को साइबर अपराधों के बढ़ते खतरों के बारे में भी विस्तार से बताते हुए सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से चैट, फर्जी आईडी, ओटीपी, लिंक व बैंकिंग जानकारी साझा न करने की सलाह दी। उन्होंने महिला हेल्पलाइन 1090, आपातकालीन नंबर 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, साइबर हेल्पलाइन



सहित अन्य हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देते हुए किसी भी प्रकार की घटना या शंका की स्थिति में तुरंत शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया गया।

सुनगढ़ी पुलिस द्वारा चलाए जा रहे इस जनजागरूकता अभियान का उद्देश्य क्षेत्र की बालिकाओं व महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाना, उनके अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाना तथा उन्हें कानूनी व साइबर सुरक्षा संबंधी बुनियादी जानकारी उपलब्ध कराना है पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मिशन शक्ति-5 के तहत इस प्रकार के कार्यक्रम आगे भी निरंतर रूप से आयोजित किए जाएंगे, ताकि हर स्तर पर महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण को मजबूती दी जा सके।

अमरिया में राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार का जनसंपर्क: क्षेत्रवासियों से सौहार्दपूर्ण संवाद, समस्याओं का आश्वासन

(जीएनएस)। पीलीभीत,अमरिया,उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने सोमवार को अमरिया क्षेत्र में ग्रामीणों के साथ सीधा जनसंपर्क स्थापित किया। उन्होंने क्षेत्रवासियों से सौहार्दपूर्ण संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और तत्काल समाधान का आश्वासन दिया। यह कार्यक्रम स्थानीय विकास और जनकल्याण को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। क्षेत्र के विभिन्न गांवों से सैकड़ों ग्रामीण मंत्री जी के सम्मान में एकत्र हुए। संजय सिंह गंगवार ने सबसे पहले अमरिया के बाजार मैदान पर आयोजित सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, "सरकार की नीतियां जन-केन्द्रित हैं। आपकी हर समस्या मेरा दायित्व है। भूमि विवाद, सड़क

निर्माण, जलापूर्ति और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।



"ग्रामीणों ने अपनी शिकायतें रखीं, जिनमें खराब सड़कों का मुद्दा प्रमुख था। एक बुजुर्ग किसान ने बताया, 'हमारे गांव की सड़क वर्षों से टूटी

पड़ी है, जिससे आने-जाने में भारी परेशानी होती है।' मंत्री जी ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए

की, जिस पर गंगवार ने महिला सशक्तिकरण योजनाओं का विस्तार करने का वादा किया।

कार्यक्रम के दौरान मंत्री जी ने क्षेत्र की कानून-व्यवस्था पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा, "पीलीभीत और शाहजहांपुर जिले में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस महकमे को सतत निर्देश दिए जा रहे हैं। कोई भी असामाजिक तत्व बख्शा नहीं जाएगा।" ग्रामीणों ने इस पर तालियां बजाकर समर्थन जताया।

संजय सिंह गंगवार ने अंत में क्षेत्रवासियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि वे नियमित रूप से जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक, जिला प्रशासन के अधिकारी और भाजपा कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। यह आयोजन न केवल प्रशासनिक दूरी को कम करने वाला था, बल्कि ग्रामीणों में उत्साह का

कि अगले 15 दिनों में मरम्मत कार्य प्रारंभ हो। इसी तरह, महिलाओं ने स्वयं सहायता समूहों के लिए अधिक प्रशिक्षण और ऋण सुविधा की मांग

प्रशस्ति पत्र देकर शिक्षक को किया सम्मानित

(जीएनएस)। लखनऊ। भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ द्वारा लखनऊ कार्यालय एक समारोह में रायबरेली के शिक्षक मोहम्मद वसीम को प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया। कोई भी सफलता संघर्ष के बिना संभव नहीं है' संघर्ष से सीखना व्यक्ति में आत्मविश्वास का भाव पैदा करता है इससे नई क्षमताएं विकसित होती हैं। और समस्याओं को सुलझाने के नए

तरीके सुझित होते हैं ' जब हम किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना करते हैं तो हमें अपनी सीमाओं और क्षमताओं का बेहतर आकलन करने का मौका मिलता है' इस तरह हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और पाते हैं की चुनौतियों का सामना कैसे किया जा सकता है' यह विचार मोहम्मद वसीम प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय गौवा बाजार सलोन ने लखनऊ में सत्र 2024- 25 में निपुण

विद्यालय होने पर आयोजित कार्यक्रम के सुअवसर पर माननीय अमील शम्सी प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ भाजपा उत्तर प्रदेश के कर कमलोंद्वारा निपुण विद्यालय प्रशस्ति पत्र मिलने के बाद कहे' अमील शम्सी ने कहा कि हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों कर्मचारियों को समय-समय पर उनके द्वारा किए गए नए प्रयासों के लिए सम्मानित करती है' मोहम्मद



वसीम को सम्मान मिलने के पश्चात सलोन के शिक्षकों ने हर्ष व्यक्त करते हुए मंत्री के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है तथा मोहम्मद वसीम को बधाई दी है' बधाई देने वालों में अध्यक्ष एवं मंत्री प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ, सेवानिवृत्त शिक्षक संगठन के साथ-साथ समाजसेवी भी शामिल हैं। विशेष रूप से मोहम्मद इस्माइल खान, अजय सिंह,सै० साजिद अली जैदी, बीना, बबली गुप्ता, लालता प्रसाद, हर्ष बहादुर सिंह तलत एजाज, पूर्व सभासद इसरार हैदर रानु, इरफान सिद्दीकी, शरीफ रायनी ,राजेश मिश्र, गौरव शर्मा, मोहम्मद कासिम हुनर, अब्दुल वहाब, मौलाना इनायत उल्लाह, अबुल हसन, माहताब खान, महफूज हक आदि ने मोहम्मद वसीम की इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त किया है'

से लगभग आधे घंटे तक बड़े वाहनों का आवागमन बाधित रहा, जबकि बाइक सवार निकलते रहे।



कि सड़क की मरम्मत के लिए ठेकेदार ने उसे उखाड़ दिया था। इसी खराब सड़क के कारण ट्रॉली पलटी। घटना

मुख्य मार्ग पर पाकड़ का पेड़ बना खतरा: कल्यानपुर पुलिया चौड़ीकरण के बाद पीडब्लूडी की अनदेखी

(जीएनएस)। पीलीभीत,गजरोला थाना क्षेत्र में माधोटांडा-पीलीभीत रोड पर स्थित कल्यानपुर नौगवां पुलिया के चौड़ीकरण कार्य के बाद मुख्य मार्ग के बीचोंबीच एक बड़ा पाकड़ का पेड़ आ गया है।

इस पेड़ के कारण वाहनों को आने-जाने में भारी खतरा बना हुआ है और अब तक कई सड़क हादसे हो चुके हैं।

स्थानीय लोगों की शिकायतें और ढहऊ की लापरवाही: स्थानीय ग्राम प्रधान पति शांति स्वरूप सोनकर ने इस खतरनाक स्थिति को लेकर लोक निर्माण विभाग (ढहऊ) से कई बार शिकायत की, लेकिन विभाग ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।

ग्रामीणों का कहना है कि पुलिया चौड़ीकरण के दौरान पेड़ को ध्यान में नहीं रखा गया, जिससे सड़क का मध्य भाग संकरा हो गया है। इस उदासीनता से लोगों में भारी

रोष व्याप्त है और वे चिंतित हैं कि किसी बड़े हादसे का कारण न बन जाए।

माधोटांडा रोड पर पुलिया संबंधी समस्याएं पहले से ही चर्चा में हैं, जहां बाढ़ और निर्माण कार्यों से आवागमन



अब तक हुए हादसे और खतरे की आशंका: इस क्षेत्र में पाकड़ के पेड़ से जुड़े हादसे पहले भी हो चुके हैं, जैसे गजरोला-पीलीभीत हाईवे पर बस का पेड़ से टकराना।

प्रभावित रहा है विशेषज्ञों के अनुसार, सड़क चौड़ीकरण में वृक्षों की स्थिति का आकलन अनिवार्य होता है, लेकिन यहां ढहऊ की लापरवाही साफ दिख रही है।

घायल मगरमच्छ की जान बचाई, गौ सेवा टीम और वन विभाग ने किया सराहनीय कार्य

(जीएनएस)। पीलीभीत,उदय करणपुर,उदय करणपुर के निवासी दीदार सिंह ने सुबह 8 बजे गणेश जी, गोपाल जी एवं ठाकुर शिवम भदोरिया को सूचना दी कि उनके खेत में नहर से एक घायल मगरमच्छ लेटा हुआ है। सूचना मिलते ही ठाकुर शिवम भदोरिया, गणेश जी, गोपाल जी एवं जंगली जानवरों में रुचि रखने वाले अदनाम खान मौके पर पहुंचे।

प्राथमिक उपचार और वन विभाग को सूचना मौके पर मगरमच्छ की जख्मी हालत देखकर टीम ने तत्काल वन विभाग पूरनपुर को सूचना दी। सभी ने मिलकर बीटाडिन स्प्रे से जख्म साफ किए और मगरमच्छ को पिंजरे में बंद कर वन विभाग को सौंप दिया। डॉक्टर अमरेश गंगवार के साथ वन विभाग पहुंचने पर मगरमच्छ के जीव और मुंह



के खराब हिस्से को काटा गया तथा बचे मुंह पर बैंडेज की गई।

निरंतर इलाज और रिहाई की योजना

टीम ने मुंह साफ कर दवाइयां लगाई और रात में हाथ से खाना खिलाया। ठाकुर शिवम भदोरिया ने बताया कि जब तक मगरमच्छ पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाता, रोज सुबह-शाम डॉक्टर अमरेश गंगवार के साथ उनका इलाज किया जाएगा। स्वस्थ होने पर वन विभाग उसे जंगल में

आजाद करेगा तथा विभाग खाने-पीने की जिम्मेदारी निभा रहा है।

विशेष सहयोगकर्ता "ठाकुर उद्देश्य सिंह जादौन, अदनाम खान, कपिल सर, सुरेश सर, गणेश जी, गोपाल जी, दीदार सिंहवन विभाग पूरनपुर

ठाकुर शिवम सिंह भदोरिया गौ सेवा टीम पूरनपुर राष्ट्रीय बजरंग दल पूरनपुर अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद

मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराना ग्रामीण को पड़ा भारी, ग्राम प्रधान ने किया हमला

(जीएनएस)। पीलीभीत। बीसलपुर क्षेत्र के एक गांव में मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने पर ग्राम प्रधान द्वारा एक ग्रामीण से मारपीट करने का मामला सामने आया है। प्रधान ने ग्रामीण को एससी-एसटी एक्ट में फंसाने की धमकी भी दी। पुलिस ने आरोपी ग्राम प्रधान के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज

कर ली है।कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बसारा निवासी अतुल कुमार पुत्र पीताम्बर देव ने तहरीर में बताया कि उन्होंने 18 नवंबर को मुख्यमंत्री पोर्टल पर खलिहान की सार्वजनिक भूमि की माप कराने से संबंधित शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि इस भूमि पर वर्तमान ग्राम प्रधान प्रवीण कुमार पिंटू ने पक्का मकान बना रखा है।अतुल

के अनुसार, शिकायत की जानकारी होने पर ग्राम प्रधान ने उन्हें धमकाया और गाली-गलौज की। विरोध करने पर प्रधान ने उनके साथ मारपीट भी की।बीसलपुर कोतवाल संजीव कुमार शुक्ला ने बताया कि तहरीर के आधार पर ग्राम प्रधान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की विवेचना की जा रही है।

मुख्यमंत्री के आदेश को ठेंगा दिखाते एलडीए के जिम्मेदार अधिकारी और बिल्डर

बड़े बिल्डर के आगे विकास प्राधिकरण के अधिकारी नतमस्तक (जीएनएस)।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ क्षेत्र में बिल्डर और एलडीए के क्षेत्रीय अधिकारियों की सांठगांठ से जोन 7 में थाना सहादतगंज, बाउली चौकी पत्थरकटा मस्जिद के पास तिराहे पर मॉडल शॉप के पहले उसी के बगल मे हो रहा है बेसमेंट के साथ अवैध कामर्शियल बिल्डिंग का निर्माण कार्य आप को बताते चलें की बेसमेंट के साथ बनकर तैयार हो रहा है ये निर्माण। बिना सीटबैक छोड़े बनाया गया साथ ही उसमे 4 स्लेप भी डाल दी है निर्माण लगभग बनकर तैयार है जोकि मानक के विपरीत है अवैध रूप से बेसमेंट खोद कर मॉर्फिट बनकर तैयार हो रही है। साथ मे उसी के ऊपर मकान भी एलडीए द्वारा कार्यवाही के नाम पर कुछ नहीं किया जाता। लखनऊ विकास प्राधिकरण के नियमो को ताख पर रखकर हुए अवैध निर्माण के एवज में ये माना जाए कि उठी है मोटी रकम। अवैध रूप से निर्माण कार्य पूरा होते समय विभागीय जिम्मेदार बने रहते है मूक दर्शक अवैध रूप से खड़ा हो रहा है इन निर्माण दे रहा विकास प्राधिकरण के नियमो को



चुनौती। इस तरह से हो रहे अवैध निर्माण का कौन है जिम्मेदार? और किसकी है जवाब देही या फिर इनको उच्च अधिकारियों का प्राप्त है संरक्षण

अब देखने वाली बात यह होगी कि इस अवैध निर्माण पर होती है कोई कार्रवाई या ऐसे ही बनकर तैयार हो जाएगी मार्केट।

विभाग का जवाब और आश्वासन ढहऊके जुनियर इंजीनियर (खए) नवनीत सकीना ने बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं था। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने के बाद पेड़ को तत्काल हटाने की व्यवस्था की जाएगी।

स्थानीय लोग अब खए के आश्वासन पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

ग्रामीणों की मांगें ■ पेड़ को 24 घंटे के अंदर हटाने की कार्रवाई हो। ■ सड़क सुरक्षा के लिए बैरियर और साइन बोर्ड लगाए जाएं ■ ढहऊ द्वारा नियमित निरीक्षण और रखरखाव सुनिश्चित किया जाए। यह घटना पीलीभीत में सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाती है, जहां हाल ही में करोड़ों की सड़कें जर्जर हो चुकी हैं। जागरूक नागरिकों से अपील है कि ऐसी समस्याओं की सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दें।



जिले के मौनिरामपुर उपज़िला में 5 जनवरी (सोमवार) को हिंदू युवक राणा प्रताप बैरागी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आगामी चुनावों से हफ्तों पहले हुई इस वारदात के बाद वहां बसे हिंदुओं में दहशत और बढ़ गई है। पिछले तीन हफ्तों में बांग्लादेश के हिंदू समुदाय के सदस्यों पर यह पांचवां जानलेवा हमला है, जिसने देश भर में जारी अशांति और विरोध प्रदर्शनों के बीच कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ा दी हैं।

प्रत्यक्षदर्शियों व मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, हमला कोपलिया बाजार के भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में हुआ। अज्ञात हमलावरों ने राहगीरों के सामने बैरागी को सिर पर गोली मारी। पुलिस ने मौत की पुष्टि की है, लेकिन गिरफ्तारी या मकसद का खुलासा नहीं किया, जिससे अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय में बेचैनी बढ़ी है।

बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले चुनावों के कारण, हिंदुओं पर हुए इन हमलों की श्रृंखला ने सबका ध्यान खींचा है। बैरागी की हत्या से पहले भी हिंदू नागरिकों के खिलाफ कई हिंसक वारदातें हुई थीं, जिससे सुरक्षा और राजनीतिक तनाव जनाया है।

कौन था राणा प्रताप बैरागी? राणा प्रताप बैरागी नरैल के दैनिक 'बीडी खोबोरे' के कार्यकारी संपादक थे। उनका कोपलिया बाजार में एक बर्फ़ फ़ैक्टरी का व्यवसाय भी था, जहाँ गोलीबारी हुई। जांचकर्ताओं ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया कि हत्या का कारण उनका काम, व्यवसाय या कोई अन्य मुद्दा था।

18 सितंबर को 27 वर्षीय दीपू की पीट-पीटकर की थी हत्या

18 दिसंबर को मयमनसिंह जिले के भालुका में 27 वर्षीय हिंदू गारमेंट वर्कर दीपू चंद्र दास की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस-मीडिया रिपोर्टों अनुसार, दास पर एक फ़ैक्टरी कार्यक्रम में इस्लाम के बारे में अपमानजनक टिप्पणी का आरोप लगा था। एक बड़े समूह ने उन्हें पीटा, नग्न कर एक पेड़ से लटकाया और फिर शव को जला दिया।

हालांकि जांच में ईशनिंदा के इस आरोप को बेबुनियाद बताया। पुलिस ने लिंचिंग के संबंध में गिरफ्तारियाँ कीं। फिर भी, मानवाधिकार समूहों ने इसे उदाहरण माना कि कैसे अफवाहें और धार्मिक दावे, खासकर तनावपूर्ण राजनीतिक दौर में, अल्पसंख्यक व्यक्तियों के खिलाफ घातक भीड़ हिंसा भड़का सकते हैं।

योगी सरकार का बड़ा फैसला, पुलिस भर्ती में आयु सीमा पर तीन साल की राहत

32,679 पदों पर सीधी भर्ती में सभी वर्गों को आयुसीमा में छूट
उत्तर प्रदेश में युवाओं के हित में फिर आगे आई योगी सरकार

लखनऊ, 5 जनवरी: उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी राहत दी है। अभ्यर्थियों के हितों को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर प्रस्तावित सीधी भर्ती–2025 के लिए अधिकतम आयु सीमा में एकमुश्त तीन वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर

दिया गया है।

लाखों युवाओं को होगा लाभ
सीधी भर्ती–2025 के अंतर्गत कुल 32,679 पदों को भरे जाने के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। शासनादेश के अनुसार आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरुष/महिला), आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस (पुरुष), आरक्षी विशेष सुरक्षा बल (पुरुष), महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी, आरक्षी घुड़सवार पुलिस (पुरुष) तथा जेल वार्डर (पुरुष एवं महिला) पदों पर भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को यह आयु शिथिलीकरण एक बार के लिए प्रदान किया जाएगा।

सरकार द्वारा यह निर्णय उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली–1992 के नियम–3 के आलोक में लिया गया है। यह फैसला 31 दिसंबर 2025 को जारी भर्ती विज्ञप्ति के अनुक्रम में 5 जनवरी 2026 को जारी शासनादेश के माध्यम से लागू किया गया है, जिससे बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों को अवसर मिलेगा जो आयु सीमा के कारण अब तक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे थे।

युवाओं के हित में योगी आदित्यनाथ सरकार
योगी सरकार का यह कदम साफ संदेश देता है कि प्रदेश की सरकार युवाओं की वास्तविक समस्याओं को

समझती है और समाधान के लिए ठोस फैसले लेने से पीछे नहीं हटती। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को न्यायसंगत अवसर देना, रोजगार के अधिक से अधिक विकल्प उपलब्ध कराना और प्रशासनिक निर्णयों में संवेदनशीलता बनाए रखना योगी सरकार की कार्यशैली का हिस्सा बन चुका है। पुलिस भर्ती में आयु सीमा शिथिलीकरण का यह निर्णय न केवल लाखों युवाओं की उम्मीदों को नया बल देगा, बल्कि यह भी दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ सरकार में युवाओं का भविष्य नीति निर्धारण के केंद्र में है।

5 लाख रुपए दो नहीं तो अश्लील वीडियो... महिला को ड्राइवर पर भरोसा करना पड़ा भारी

(जीएनएस)।

लखनऊ के राजाजीपुरम इलाके से ब्लैकमेलिंग और धमकी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। एक महिला ने अपने पूर्व ड्राइवर पर अश्लील फोटो-वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने, चोरी करने और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप...

नेशनल डेस्क: लखनऊ के राजाजीपुरम इलाके से ब्लैकमेलिंग और धमकी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। एक महिला ने अपने पूर्व ड्राइवर पर अश्लील फोटो-वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने, चोरी करने और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपी महिला से 5 लाख रुपये की मांग कर रहा है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू



कर दी है।

पीड़िता के अनुसार, आरोपी हनुमान सिंह, जो राजस्थान का निवासी है, पिछले ढाई से तीन साल से उनके यहां ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा था। इस दौरान उसका घर में आना-जाना बना रहा। महिला का आरोप है कि वेतन के अलावा आरोपी ने अपनी मां के कैंसर इलाज का हवाला देकर

उनसे करीब 5 लाख रुपये उधार लिए थे और किरतों में लौटाने का भरोसा दिया था। कुछ समय पहले वह अचानक नौकरी छोड़कर गायब हो गया।

आरोपी के फरार होने के बाद जब घर का सामान चेक किया गया, तो सोने के जेवरत और लगभग 50 हजार रुपये नकद गायब मिले। पीड़िता को

आशंका है कि यह चोरी भी उसी ने की है। इसके बाद आरोपी ने फोन कॉल के जरिए महिला को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।

पीड़िता का कहना है कि आरोपी धमकी दे रहा है कि उसके पास उनके अश्लील फोटो और वीडियो हैं, जिन्हें वह सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा, अगर 5 लाख रुपये नहीं दिए गए। इतना ही नहीं, आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी, जिससे महिला और उसका परिवार दहशत में आ गया।

घटना से परेशान होकर पीड़ित परिवार ने तालकटोरा थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में थाना तालकटोरा के इंस्पेक्टर कुलदीप ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है।

'ये माननीय अध्यक्ष हैं', नितिन नबीन को नेताओं ने ऐसा क्या कहा कि हाईकमान हुई गुस्सा, भाजपा में नया प्रोटोकॉल

(जीएनएस)।

भारतीय जनता पार्टी के संगठन में इन दिनों एक वाक्य बार-बार सुनाई दे रहा है - "पद नाम से बड़ा होता है"। वजह हैं नवनि्युक्त कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन। उनके नाम को लेकर हुई एक छोटी सी 'लापरवाही' ने ऐसा संदेश दे दिया कि अब पार्टी में बोलने की भाषा तक पर अनुशासन तय हो गया है।

दरअसल नितिन नबीन उग्र और राजनीतिक अनुभव में पार्टी के कई दिग्गज नेताओं से छोटे हैं। इसी वजह से कुछ वरिष्ठ नेता अनौपचारिक बातचीत में उन्हें सीधे नाम से संबोधित कर रहे थे। बात जब ऊपर तक पहुंची, तो हाईकमान का मूड बिगड़ गया। संदेश साफ था - अब वे सिर्फ नितिन नबीन नहीं, "माननीय अध्यक्ष" हैं।

नाम नहीं, पद से संबोधन... यहीं से शुरू हुआ बवाल

हिन्दुस्तान के साप्ताहिक कॉलम 'राजरत्नार' के मुताबिक नितिन नबीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद संगठन में प्रोटोकॉल को लेकर सख्ती इसलिए बढ़ी, क्योंकि कुछ वरिष्ठ नेता निजी रिश्तों के चलते पद की गरिमा भूल बैठे थे। हाईकमान को यह संदेश गलत लगा। नेतृत्व का मानना है कि अगर शीर्ष स्तर पर अनुशासन ढीला होगा, तो नीचे तक गलत संकेत

जाएगा।

यही वजह है कि अब पार्टी ने सभी नेताओं और पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बातचीत चाहे बंद कमरे में हो या सार्वजनिक मंच पर, संबोधन हमेशा पद के अनुरूप होगा। नाम लेकर बुलाने की आदत पर अब ब्रेक लगा दिया गया है।

हाईकमान का तर्क, जुवान भी अनुशासन सीखें

भाजपा नेतृत्व का मानना है कि संगठन केवल फैसलों से नहीं, भाषा से भी चलता है। पद की गरिमा शब्दों में दिखनी चाहिए। इसलिए पुराने निजी रिश्ते, साथ की राजनीति और दोस्ती, सब एक तरफ रखकर अब पद को प्राथमिकता देने का आदेश दिया गया है।

खास बात यह भी है कि नितिन नबीन के जल्द ही पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की संभावना मानी जा रही है। ऐसे में पार्टी किसी भी तरह का भ्रम या असहजता पहले ही खत्म करना चाहती है।

नितिन नबीन की सादगी भी